

SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)



सच साबित हो रही स्वतंत्रता सेनानी का कथन बाबू रामनारायण सिंह ने संविधान सभा में रखा था वक्तव्य चतरा जिला के प्रतिनिधि की हुई थी भागीदारी

अजीत कुमार सिंह, शोधार्थी, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखण्ड, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Corresponding Author :

अजीत कुमार सिंह,

शोधार्थी, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग,
झारखण्ड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 20/08/2020

Revised on : -----

Accepted on : 28/08/2020

Plagiarism : 01% on 20/08/2020



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 1%

Date: Thursday, August 20, 2020

Statistics: 22 words Plagiarized / 2518 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

Hkkjrh; Lora=rk vkUnksyu ds bfrgki esa rRdkyhu fcgkj dk NksVkukxiqj ,d egRoiv.kZ
LFkku jllrk gSA egkRek xkj/kh ds usr'Ro esa tks vfgalkRed vkUnksyu pyk, tk jgs Fks mldk
izHkko NksVkukxiqj ds {ks=ksa ij Hkh O;kid :i Is iM+kA prjk Lok/khurk vkUnksyu dk
izeq[k dsUnz cu x;kA ftl dkjzsl dh LFkkiuk 1885 esa dh xbZ Fkh mlds usr'Ro esa ns'kHk
ds Lora=rk Isukuh xksycUn gks jgs FksA vkUnksyu dh fpaxkjh prjk esa ,slh QSyh fd blhd

शोध सार :

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में तत्कालीन बिहार का छोटानागपुर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जो अहिंसात्मक आन्दोलन चलाए जा रहे थे उसका प्रभाव छोटानागपुर के क्षेत्रों पर भी व्यापक रूप से पड़ा। चतरा स्वाधीनता आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र बन गया। जिस काँग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी उसके नेतृत्व में देशभर के स्वतंत्रता सेनानी गोलबन्द हो रहे थे। आन्दोलन की चिंगारी चतरा में ऐसी फैली कि इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। स्वतंत्रता आन्दोलन के संघर्ष में चतरा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाबू रामनारायण सिंह की भूमिका राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ये चतरा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी।

स्वतंत्रता सेनानी बाबू रामनारायण सिंह ने संविधान सभा में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा था कि अधिकारों का केन्द्रियकरण करना भविष्य के लिए सही नहीं होगा बल्कि शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण अधिक-से-अधिक किया जाना उचित होगा। इस संबंध में ग्रीनविले ऑस्टीन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि "The major power should be invested in villages then in the province and then centre." अधिकारों को एक ही स्थान पर केन्द्रित करने के सख्त खिलाफ थे बाबू रामनारायण सिंह। तत्कालीन सत्ता के क्रियाकलापों से अत्यंत क्षुब्ध थे तथा 1956 में इन्होंने एक पुस्तक "स्वराज लुट गया" की रचना की। इस पुस्तक की पष्ठ संख्या 29 में शक्तियों के केन्द्रीयकरण के खिलाफ अपने विचारों को व्यक्त किया है।

"स्वराज लुट गया" में इन्होंने कहा है कि "अधिकारों का केन्द्रीयकरण करना भारी भूल है।" राष्ट्र का विकास कैसे हो इसकी उन्हें गहरी समझ थी। आम

July to September 2020

WWW.SHODHSAMAGAM.COM

A DOUBLE-BLIND, PEER-REVIEWED QUARTERLY MULTI DISCIPLINARY
AND MULTILINGUAL RESEARCH JOURNAL

IMPACT FACTOR
SJIF (2020): 5.56

733

भारतीयों की जो अपेक्षाएँ थी अपने राष्ट्र से उसकी पूर्ति कैसे हो इसके लिए बाबू रामनारायण सिंह के पास दूरदृष्टि थी। इनका स्पष्ट मत था कि सरकार को चाहिए कि शक्तियों का विभाजन बिल्कुल नीचले पायदान तक हो। ऐसा करने से लोकतंत्र मजबूत होगा। शासन सत्ता पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जन सहभागिता से समाज में एक बेहतर माहौल बनेगा और सच मायने में तभी स्वतंत्रता के लक्ष्यों को हम प्राप्त कर पायेंगे।

शासन व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण जितना अधिक निचले स्तर तक होगा आमजनों की शासन में भागीदारी उतनी ही अधिक एवं सक्रिय होगी। इसलिए केन्द्रिय सत्ता से लेकर पंचायतों तक शासन व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण करने की वकालत बाबू रामनारायण सिंह ने संविधान सभा में विचारों को व्यक्त करते हुए की थी। इन्होंने एक ऐसी शासन व्यवस्था के बारे में सोचा था जो जनता के प्रति जिम्मेदार हो एवम् जनता का कल्याण करना ही शासन का केन्द्रबिन्दु हो। समाज में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा आदि को इन्होंने बहुत करीब से देखा और महसूस किया था। इसलिए सदैव ही शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की वकालत की। क्योंकि इनका स्पष्ट मानना था कि चीजों को केन्द्रीकृत कर हम समाज का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएँगे।

राष्ट्रीय आन्दोलन में चतरा से जो स्वतंत्रता सेनानी उभरे उनका प्रभाव बहुत ही व्यापक रूप से इस क्षेत्र पर पड़ा। इसके अध्ययन से चतरा जिले के गौरवशाली इतिहास से वर्तमान पीढ़ी को ज्ञान होगा तथा उनके भीतर गौरव का बोध होगा। नई पीढ़ी को यह दायित्व का बोध कराना भी उद्देश्य है कि किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अनगिनत मुसिबतों को झेलते हुए राष्ट्र की सेवा की। निश्चित रूप से इस कार्य से कई ऐसी जानकारियाँ तथा तथ्य सामने आएँगे जो अब तक हमारे बीच उभर कर नहीं आ पाएँ हैं।

मुख्य शब्द :

स्वाराज, लोकतंत्र, राष्ट्रीय, आन्दोलन, विकेन्द्रीकरण, अशिक्षा, गरीबी, संविधान सभा के सदस्य एवम् स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बाबू रामनारायण सिंह की भूमिका।

प्लासी के युद्ध ने भारत को दासता के जुए में बाँध दिया, तो बक्सर के युद्ध ने दासता की बेड़ी को और ज्यादा जकड़ दिया। 1857 ई० के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया, लेकिन क्रांति को दबा दिया गया। परन्तु इस सशस्त्र क्रांति की चिंगारी दबी नहीं। परिणामस्वरूप 1885 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसकी स्थापना के पीछे प्रारंभिक उद्देश्य भारतीयों की मांगों को उचित मंच के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता के समक्ष उठाना था। स्वतंत्रता आन्दोलन में चतरा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ के कई स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गाँधी के नेतृत्व में देशभर में चलाए जा रहे आन्दोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। बाबू रामनारायण सिंह की भूमिका राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। ये चतरा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी।

बाबू रामनारायण सिंह का जन्म वर्तमान चतरा जिलान्तर्गत हंटरगंज थाने में तेतरिया ग्राम में सम्वत् 1941 (ई० 1885) पौष मास शुक्ल पक्ष द्वितीया को हुआ था। इनके पिता का नाम स्व० बाबू भोलीसिंह था। जो एक साधारण किसान थे तथा फारसी भाषा के बहुत बड़े जानकार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा छोटकी जोरी लोअर प्राइमरी स्कूल से हुई। उसके बाद हंटरगंज अपर प्राइमरी स्कूल तथा 1900 में छात्रवृत्ति के साथ अपर प्राइमरी परीक्षा जोरी मिडिल वर्नाक्युलर स्कूल से 1902 में मिडिल परीक्षा पास की।

इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ते चले गए तथा 1911 में 'सेन्ट जेवियर' कॉलेज से आई० ए० की परीक्षा पास की। इसके बाद 1913 ई० में रिपन कॉलेज से बी०ए० की परीक्षा पास की। इन्होंने कानून की शिक्षा भी प्राप्त की। "असिस्टेंट सेटेलमेंट आफिसर" के पद पर नियुक्त होकर लगभग दो वर्षों तक सरकारी नौकरी भी की। पटना में वकालत भी की अभी लगभग वकालत एक वर्ष पूर्ण होने ही वाला था कि महात्मा गाँधी ने अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन शुरू करने की घोषणा की जिससे प्रभावित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता आन्दोलन में कूद पड़े।

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान बाबू रामनारायण सिंह को कुल आठ बार जेल जाना पड़ा। चतरा के क्रांतिकारी महात्मा गाँधी के आह्वान पर मर-मिटने के लिए तैयार हो गए। बाबू रामनारायण सिंह तथा सुखलाल सिंह को गिरफ्तार कर केन्द्रिय कारागार हजारीबाग भेज दिया गया। 9 नवम्बर 1942 को दिवाली की अँधेरी रात में बाबू रामनारायण सिंह ने जेल में बन्द अन्य प्रमुख नेताओं के साथ जेल से भागने की योजना बनाई तथा देश के छह राष्ट्रीय नेता जेल से भागने में सफल रहे। जिसमें जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, योगेन्द्र शुक्ल, सुरजनारायण सिंह, शालीग्राम सिंह तथा गुलाबी स्वर्णकार शामिल थे।

देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में बाबू रामनारायण सिंह तथा शालीग्राम सिंह की भूमिका की काफी प्रशंसा की है। बाबू रामनारायण सिंह के दबाव एवं विशेष आग्रह के ही कारण 1940 में अखिल भारतीय काँग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रामगढ़ में सम्पन्न हुआ। बाबू रामनारायण सिंह स्वागताध्यक्ष थे, किन्तु उन्होंने यह दायित्व बाबू राजेन्द्र प्रसाद को सौंप दिया था। इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीतकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया एवम् गाँधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहे। इन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में अपने महत्वपूर्ण विचारों को रखा एवम् शक्ति के विकेन्द्रीकरण करने की बात को बहुत ही जोरदार तरीके से उठाई।

स्वतंत्रता सेनानी बाबू रामनारायण सिंह ने संविधान सभा में अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहा था कि अधिकारों का केन्द्रियकरण करना भविष्य के लिए सही नहीं होगा। इस कथन की चर्चा ग्रीनविले ऑस्टीन ने अपनी पुस्तक 'द कार्नरस्टोन ऑफ इंडियन कांस्टीच्यूशन' के पृष्ठ संख्या 34 में की है। उसमें लिखा गया है कि "The major power should be invested in villages, then in the province and then centre."

इसके पश्चात् रामनारायण बाबू ने तत्कालीन सत्ता के क्रियाकलापों से क्षुब्ध होकर एक पुस्तक 'स्वराज लुट गया' की रचना की थी। 1956 ई० में प्रकाशित इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 29 में भी इसका विशद वर्णन है। इस दुर्लभ पुस्तक के कुछ अंश को प्रस्तुत करना समीचीन होगा जिसमें लिखा गया है कि :

"अधिकार का केन्द्रीयकरण करना भारी भूल है।" राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन में बाबू रामनारायण सिंह ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। राष्ट्र का विकास कैसे हो, आम जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे हो इसकी उन्हें गहरी समझ थी। आम भारतवासियों की जो अपेक्षाएँ थी उनकी पूर्ति हेतु बाबू रामनारायण सिंह के पास दूरदृष्टि थी।

बकौल लेखक देश में शासन या सरकार के नाम में या अन्य किसी नाम में देश की रक्षा, शान्ति और उन्नति के लिए कोई राष्ट्रीय प्रबन्ध तो अभी आवश्यक है। लेकिन स्वराज्य के वास्तविक सिद्धांत के अनुसार इस सम्बन्ध का उत्तरदायित्व और अधिकार केन्द्रीभूत न होकर उसका विकेन्द्रीय होना आवश्यक है। लेकिन इस सरकार की नीति के अनुसार मालूम हो रहा है कि सत्ताधारी लोग सभी अधिकारों को केन्द्रीभूत करके अधिकारों में रखना चाहते हैं। अंग्रेजी राज्यकाल में म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल बोर्ड आदि स्थानीय संस्थाओं का निर्माण हुआ था, जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कई विषयों का अधिकार दिया गया था। लेकिन इस सरकार की नीति से ऐसा झलक रहा है, कहीं-कहीं सत्ताधारी लोग इस तरह की घोषणा भी कर देते हैं कि अब इन संस्थाओं की आवश्यकता नहीं रह गई है और इस नीति के अनुसार उनके अधिकार भी धीरे-धीरे छीने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए बिहार राज्य के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लिया जा सकता है। अंग्रेजी राज्य काल में जिला बोर्ड को प्राइमरी शिक्षा सम्बन्धी प्रायः सभी अधिकार थे। लेकिन अभी वे प्रायः अधिकार छीन लिए गए हैं। ऐसी भूलें राज्य सरकारों को कभी नहीं करनी चाहिए थी। राज्य सरकार का एकमात्र कार्य पवित्र और सहानुभूतिपूर्ण निरीक्षण का होना चाहिए था। बिहार राज्य या अन्य सभी राज्य सरकारों की जरूरत इसलिए हुई कि दिल्ली की केन्द्रीय सरकार इसका ठीक-ठाक प्रबन्ध नहीं कर सकती थी।

शासन व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण जितना निचले स्तर तक होगा आमजनों की शासन में भागीदारी उतनी ही अधिक एवम् सक्रिय होगी। इसलिए केन्द्रीय सत्ता से लेकर पंचायतों तक शासन व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण करने की वकालत बाबू रामनारायण ने संविधान सभा में विचारों को व्यक्त करते हुए की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी भी प्रारंभ से ही सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बड़े समर्थक थे। इसी तरह हर राज्य सरकार को यह मान लेना चाहिए कि जिलों

में और गाँवों में ठीक-ठीक प्रबन्ध नहीं कर सकते। जिलों का सारा प्रबन्ध जिले वाले ही कर सकते हैं और गाँव का प्रबन्ध गाँव वाले ही कर सकते हैं। जिस सिद्धांत के मुताबिक देश में सारा अधिकार केन्द्रिय सरकार में केन्द्रीभूत नहीं होना चाहिए और उसी कारण से प्रान्तीय अर्थात् राज्य सरकारों की आवश्यकता पड़ी, उसी तरह जिला सरकार और गाँव सरकार की जरूरत है। पर दुःख है कि कोई सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। जब ईमानदारी का अभाव है, तो इनके जरिए जो अनर्थ न हो यही आश्चर्य है। अनर्थ ही करना तो इनका स्वभाव हो रहा है। परिस्थिति भयानक है। इस पर देशवासियों को विचार करना परमावश्यक है।

बाबू रामनारायण सिंह सदैव राजनीतिक सुचिता के हिमैती रहें। इन्होंने एक ऐसी शासन व्यवस्था के बारे में सोचा था जो जनता के प्रति जिम्मेदार हो एवम् जनता का कल्याण ही शासन का केन्द्र बिन्दु हो। आम जनमानस में गरीबी, अशिक्षा व्याप्त थी इसे उन्होंने बहुत करीब से देखा था इसलिए इन्होंने सदैव ही केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति का विरोध किया एवम् कहा कि इससे जनता का सर्वांगीण विकास कभी पूरा नहीं हो पाएगा तथा जो आजादी हम सब ने पायी है उसके उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएँगे। इसलिए बाबू रामनारायण सिंह ने कहा कि आजकल कितनी बड़ी धोखेबाजी की बात है कि भारतीय नेता जो अभी शासक भी है महात्मा गाँधी जी की सदा दुहाई देते रहते हैं। अपने व्यवहार में महात्मा गाँधी का एक भी उपदेश या सिद्धांत नहीं मानते। वे नेता और शासक जनता से बराबर कहा करते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारे देश में गोलीकांड आजकल हो रहे हैं, उतने गोलीकांड इस देश में शायद संसार के किसी देश में नहीं हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद काँग्रेस की नीति उन उद्देश्यों से भटक गई जिनको लक्ष्य मानकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि काँग्रेस भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था के राह पर चल रही है इसलिए बाबू रामनारायण सिंह ने काँग्रेस की कुप्रवृत्ति के खिलाफ आवाज उठाई एवम् उसे सतर्क किया। देश के स्वतंत्र होने के बाद महात्मा जी ने आदेश दिया कि काँग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। इस समय यह स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा करना देश के हित में अनिवार्य था। लेकिन काँग्रेस के अन्य नेताओं ने केवल स्वार्थ साधन के अभिप्राय से इसको नहीं माना। काँग्रेस का उज्ज्वल इतिहास मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जो काँग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था थी, देश का सारा शासन भार अधिकार में आ जाने के बाद नेताओं ने इसे एक राजनैतिक दल करार दे दिया। यह साधारण अनर्थ नहीं हुआ है। काँग्रेस के नाम में सारे देश में बहुत जायदादें थी और वे वास्तव में जनता की थी, लेकिन आज वे सभी सम्पत्तियाँ एक दल विशेष की हो गई हैं। इतना ही क्यों, अभी सरकार उनकी कचहरियाँ, उनकी पुलिस, उनकी पलटन संक्षेप में सारे देश की सभी सम्पत्तियाँ उनकी हो गई हैं। देश में अभी कोई चीज ऐसी नहीं रह गई है, जो उनकी नहीं है। यही नेतागण चिल्ला-चिल्लाकर कहा करते थे कि अंग्रेज देश को लूट रहे हैं और शासन में भी जरूरत से बहुत अधिक खर्च करते हैं। इन नेताओं को अब चाहिए था कि शासन खर्च कुछ कम करें लेकिन कम करने के बदले खर्च कई गुणा बढ़ा दिया गया। नए-नए महकमों की स्थापना हो रही है। सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की तो अब गिनती करना कठिन है। करों की संख्या घटने के बदले बराबर बढ़ती जा रही है। मालूम होता है कि सारे देश में लूट मची हुई है। बिहार-बंगाल की जमींदारी, उत्तर प्रदेश की ताल्लुकदारी और राजस्थान की जागीरदारी प्रथायें किसानों को शोषण से बचाने के अभिप्राय से कानूनन उठाई गई, लेकिन पहले के एक शोषक की जगह सरकारी कर्मचारियों के रूप में अब अनेकों के अत्याचार से किसानों के कष्टों की सीमा ही नहीं रही है।

निष्कर्ष :

भारतवर्ष को स्वतंत्रता कोई पुरस्कार स्वरूप अंग्रेजों से प्राप्त नहीं हुई थी इसके लिए असंख्य बलिदान स्वतंत्रता सेनानियों ने दिए थे। यही कारण है कि जब बाबू रामनारायण सिंह ने बहुत ही करीब से देखा कि काँग्रेस में कई रोग समाते जा रहे हैं और यह जनता के उम्मीदों को पूरा कर पाने में पूर्ण रूप से सामर्थ्य नहीं हो पा रही है तो इसकी आलोचना भी किए। क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व काँग्रेस एक अखिल भारतीय मंच था जहाँ सभी इकट्ठे होकर अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलन चला रहे थे इसलिए स्वाभाविक था कि काँग्रेस से ही सबसे अधिक अपेक्षाएँ देश की जनता को होगी। पूज्य बापू ने भी अपने जीवनकाल में ऐसा कभी नहीं सोचा होगा, उनकी अमर आत्मा यह जानकर स्वर्ग में अभी रोती होगी कि उनके तथाकथित अनुयायी लोग इस तरह देशवासियों को तबाह और बर्बाद कर रहे

हैं। अपने-अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर या धर्म और ईमान के नाम पर ही सही, ये नेता और शासक लोग जो चाहें सो करे, पर ऐसे-ऐसे अवसरों पर उनको न गाँधी जी का नाम ही लेना चाहिए और न गाँधी जी के आदेशों की शरण लेनी चाहिए।

बाबू रामनारायण सिंह सच्चे मायने में एक समाज सुधारक, गाँधीवादी चिंतक तथा राजनेता थे। इन्होंने सदैव आमजनता के हितों को प्राथमिकता में रखा। संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्होंने बड़े ही प्रखर रूप में अपने विचारों को रखा। संसद के सदस्य होने के नाते भी इन्होंने सदन में सदैव जनसरोकार के मुद्दों को उठाया एवम् आवश्यकता पड़ने पर सरकार भी नीतियों की भी कड़ी आलोचना की। चतरा जिला को अपने इस महान सपूत पर गर्व हमेशा रहेगा जिसने इस क्षेत्र की पहचान को राष्ट्रीय फलक पर पहुँचाया। भारतवर्ष की स्वतंत्रता आन्दोलन एवं स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चा जब भी होगी चतरा के इस महान सपूत का नाम बड़े ही आदर और गर्व के साथ लिया जाएगा।

संदर्भ सूची :

1. स्वराज लूट गया, बाबू रामनारायण सिंह, दिल्ली, 1956।
2. संसदीय राजनीति कोष भाग-I, शब्दार्थ प्रकाशन, झारखण्ड, राँची-2011।
3. द इंडियन कांस्टीयूशन : 'कार्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ऑक्सफोर्ड प्रेस, 1999।
4. दत्त के०के०, (2014) बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास (खण्ड-3), बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
5. दैनिक हिन्दुस्तान, राँची, 15 अगस्त 2003।
6. दैनिक प्रभात खबर राँची, 15 अगस्त 2020।
7. कहानी झारखण्ड आन्दोलन की, बलबीर दत्त, क्राउन पब्लिकेशन्स, 2014।
8. आत्मकथा- डॉ० राजेन्द्र प्रसाद।
9. स्वतंत्रता आन्दोलन की बिखरी कड़ियाँ, प्रभुनारायण विद्यार्थी।
10. आदिवासी अस्तित्व और झारखण्ड अस्मिता के सवाल, डॉ० रामदयाल मुण्डा, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।
11. तिवारी, रामकुमार, (2019), झारखण्ड की रूप रेखा, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना।
12. सिंह, बीरकेवर प्रसाद, (1998), राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारतीय शासन, भारती भवन, पटना।
